यात्रा आमंत्रण

भारत की एकमात्र हिंदी पर्यटन पत्रिका

जनवरी-मार्च २०२२
अंक पांचवा
मूल्य ८०

प्रगतिहीनता का कालचक्र उत्तर प्रदेश

Hunza Tea

DRINK TO YOUR HEALTH

Hunza Tea

An Ayurvedic Product

चाय नहीं → हुंजा टी (Hunza Tea)
सेहत के लिए आदत बदलो

Hunza Tea leaves consist of natural ingredients, namely holy basil, mint, cardamom, cinnamon and ginger. These ingredients have never been processed with chemicals, additives or preservatives. This natural drink forms an essential part of the diet of the Hunza people.

MRP 350/-
(incl. of all taxes)

Buy online at www.biswaroop.com/shop | Call: +91-9312286540

पुणे की
सुप्रसिद्ध

काळजे मिसळ हाउस ®

KALJE
SPECIAL
MISAL

Call Us For
Beverages Outlet
Launching On
New Year
2022.

सुप्रसिद्ध
पैलवान वडा

कोल्हापुरी चवीचा रांगडा !!

Come & Experience It.

Franchise Opportunity
9049487878

Benefit To Get Franchise
- Fastest Growing Misal Brand Among Family.
- Great Taste And Assurence Of Quality.
- Unique Trendy Menu.
- We Provide Training, Marketing, Branding And Support.
- Raw Material Provide By Us.
- Own Production Strength.

Follow Us kaljemisalhause

Shop NO. B1 Privia Mall Near PCMC New RTO
Sector 6 Moshi Pradhikaran Pune 411062.

कवर पृष्ठ सकल्पना

समय का चक्र निरंतर चलता रहता है और इसी चलते चक्र को कालचक्र कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो काल का अर्थ होता है निरंतर चलने वाला समय का चक्र। नागा साधु महादेव को अपने आराध्य के रूप में पूजते है। महादेव यानि भगवान् शिव को समय का अवतार माना जाता है। प्रगति का चक्र समय के साथ आगे बढ़ता है और उसी से तय होता है हमारी उन्नति और अवनति। समय का कालचक्र क्या सोचता है देश के सबसे बड़े राज्य को लेकर। यह अंक उस और इशारा है।

- **Maharashtra Bureau Chief**
  Nitin Kalje
- **Mumbai Head**
  Narender H Patil
- **Video Editor & Delhi Head**
  Kapil KUMAR Attri
- **IT Head**
  Shantanu Chauhan
- **Publishing Consultant**
  Shankar singh KorAnga
- **Content Contributor**
  Chetan Vadher
  (Mandiro ka Bhavya Itihaas)
  Adarsh Dhawan
  (Corona ke Naam par Sazish)
- **Consulting Editor**
  Mohammad Ismail

- Visit us and download the PDF copy at www.yatramantran.com
- Yatra Amantran invite all travel professional to list their business in our website. Also share press release/news/views at yatraamantran@gmail.com

- **Editorial Team**
  Chief Editor
  Biswadeep Roychowdhury
- **Legal Advice and UP Head**
  Pratap Singh Chandel
- **Copy Editing**
  Yash Bhardwaj
- **Graphic Designer**
  Nisha Mehta
- **PRO**
  Mohan Joshi
- **Honourable Advisor**
  Gaur Kanjilal
  Executive Director, Indian Association of Tour Operator
- **Special Thanks**
  Dr Biswaroop Roychowdhury
  (Indo Vietman Medical Board)
  Mamta Shukla
  (State President, Rashtriye Lok Dal)
  Jay Prakash Pawar
  (Gen Sec, Sarv Samaj Janta Party)
  Akhilender Pratap Singh
  (Advocate, Allahabad High Court)
  Somya Dutta
  (Gen Sec, All India Bank Officer Confederation)

- Support our work through donation/advt, mail us at Biswadeep96@gmail.com
- Subscribe our You Tube Channel Asatya Bharat
- RNI Number HRAHIN/2017/72144

यात्रा आमंत्रण अपने निष्पक्ष पत्रकारिता के सिद्धांतो के साथ कटिबद्ध है। ऐसे पत्रकारिता से अगर आपको लगता है की समाज में नव चेतना का उदय होगा और सच्चाई को नई पहचान मिलेगी तो आप हमे सहयोग दे। आप के लिए पत्रिका का डिजिटल अंक मुफ्त में हमारे वेबसाइट में उपलब्ध है। उसे अपने मोबाइल में लेकर ज्यादा से ज्यादा साथिओ तक साझा करे। राजनैतिक दल या दुसरे संघटन 200 से अधिक अंक हमसे मंगवाए और उसे अपने कार्यकर्ता में वितरित करे। प्रति अंक 80 रुपये का खर्च आएगा। आप हमे विज्ञापन भी दे सकते है।
संपर्क करे कपिल अन्तरी - 9716665444 Whats app 9971229644

Publisher Address
Shop No.B1Privia Mall Near PCMC New RTO Sectore-6,Moshi Pradhikaran Pune-411062

संपादक की कलम से

Edition
March-April 2021

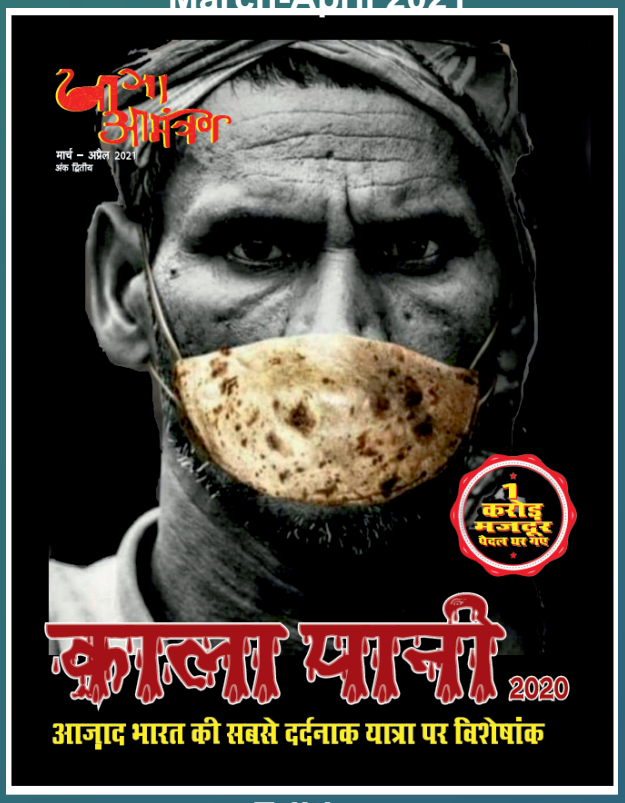

Edition
October-December 2021

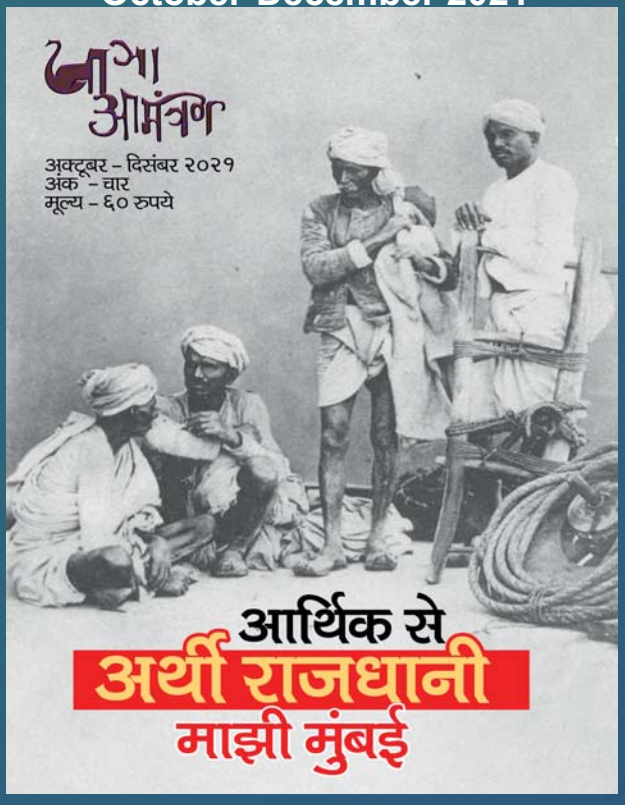

कहते है लखनऊ से होकर दिल्ली के सत्ता की चाबी पाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश तय करता है की दिल्ली का तख्त किसे मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पास है प्रधान मंत्री के पद की चाबी। यानि जिसका उतर प्रदेश उसका दिल्ली। क्या 2022 का चुनाव 2024 की पृष्टभूमि तैयार करेगा। अगर ऐसा है तो इस बार मेरी नजर उत्तर प्रदेश के विकास कार्यो पर होगी। पर साथ ही अगर भाजपा सत्ता पर काबिज होना चाहती है तो भाजपा के विकास कार्य भी गिनवाने जरूरी है। तो इस बार का अंक दो धुरी के मध्य है , एक उत्तर प्रदेश में कितना घुमा विकास का पहिया और दूसरा भाजपा ने देश को क्या दिया। पाठक इस बार उत्तर प्रदेश को 2024 के दूरदर्शिता के साथ ले और राज्य के वोटर वोट भी इसी आधार पर दे। किसानो ने तो फसल की लड़ाई जीत ली अब बारी है की देश में फैले अनियमिता की लड़ाई भी जीती जाये। तो इस बार नजर मौलिक अधिकारों के उल्लघन से लेकर कोविद के नाम पर चल अनैतिक फैसलों पर होगी।

बिस्वदीप रॉय चौधरी

विज्ञापनों में ही है गंगा नदी का विकास

कहने को तो हमारे संस्कार और आस्था का प्रतिक है गंगा नदी। महाभारत में गंगा को भीष्म पितामह के माँ के रूप में दिखाया गया है । उन्हें गंगा पुत्र के नाम से भी पुकारा जाता था। हिन्दू धर्म में माँ गंगा को पूजनीय माना जाता है और अपने पापो की मुक्ति के लिए गंगा में डुबकी लगाने को सबसे पवित्र काम माना जाता है। महाभारत में माँ गंगा ने शांतनु से विवाह किया और अपने पहले सात बच्चो को पैदा होते ही गंगा में प्रवाहित कर दिया पर आठवे पुत्र यानि देवब्रत या भीष्म पितामह को प्रवाहित नहीं कर पाई। जब शांतनु ने पूछा की वह ऐसा क्यों कर रही है तब उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के उस शाप का जिक्र किया जिसमे नंदी गाय चुराने के कारण मृत्यु लोक का शाप मिला। मान्यताओं के मुताबिक असतावासुस ने माँ गंगे से कहा की उनके कोख से जन्म लेना चाहते है और जैसे ही वह पैदा हो उन्हें गंगा में प्रवाहीत कर दिया जाये। इस तरह से वह अपने शाप से मुक्त हो जायेंगे। एक माँ के लिए अपने बच्चे को जल में प्रवाहीत करना कितना कठिन होगा पर शाप से मुक्ति के लिए ऐसा किया गया । पर भीष्म पितामह को वह नहीं प्राविहत कर पाई और आगे का इतिहास आपको मालूम ही है। पर आज वही गंगा जो माना जाता है की महादेव के जटाओ से होते हुए उत्तर भारत में बहती है , वह दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी है। हजारो करोडो रूपये इस नदी के सफाई के नाम पर खर्च कर दिए गए पर परिणाम कुछ नहीं। नवमी गंगा परियोजना के लिए 20 हजार करोड़ के राशि का आवंटन हुआ जिसमे से अकेले कानपूर शहर के लिए हजार करोड़ था। पर क्या परिणाम हुआ वह समझिये। गंगा नदी के प्रदुषण में अकेले कानपूर शहर का योगदान 75 प्रतिशत है। कानपूर के जाजमऊ इलाके में सबसे जयादा चमड़े के उद्योग चल रहे है और यही से सबसे ज्यादा प्रदुषण भी फैलता है। जिला अधिकारी कानपूर ने 93 ऐसे कारखानों को नोटिस भेजा पर कानपूर और उन्नाओ के आस पास ऐसे और 250 कारखाने चल रहे है। क्या सबको बंद करवाने का नोटिस भेजा जा सकता है। कानपूर से 330 किलोमीटर दूर है वाराणसी। **Toxix** नाम की एक संस्था ने पाया की वाराणसी के अस्सी घाट में सबसे जयादा माइक्रो प्लास्टिक पाए गए है जो हो सकता है पर्यटकों से आये हो। क्या हम इसके लिए जिम्मेदार है। हो सकता है क्युकी अगर हम अपने हाथ में रखे प्लास्टिक के बोतल या अन्य वस्तु न डाले तो।

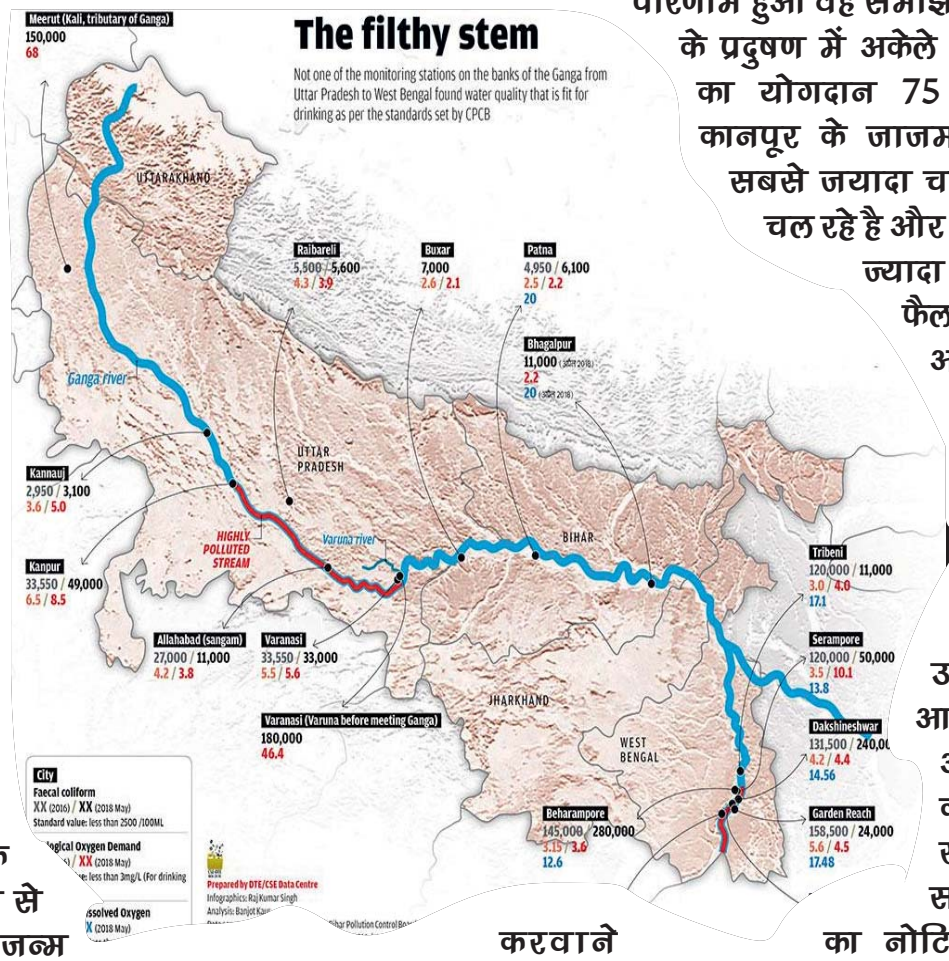

संक्षिप्त में

सबसे सुरक्षित जगह मानी है राज्य की विधान सभा भवन । वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में एक प्रकार का प्लास्टिक विस्फोटक मिला । यह विस्फोटक समाजवादी पार्टी के किसी मेंबर के सीट के निचे मिला था । जब जांच शुरू हुई तो पता चला की विधान सभा के 100 में 94 **CCTV Camera** काम नहीं कर रहे है । इस भवन में 150 आईएएस अफसरों के दफ्तर भी है । उत्तर प्रदेश में हर एक लाख आबादी में 168 पुलिस है और हर 100 पुलिस में 4 गाड़ी है।

इस वक्त गंगा तकरीबन 116 शहरों से होकर गुजरती है और औसतन इन शहरों की आबादी एक लाख से ज्यादा है। इस सब शहरों के नाली का पानी भी गंगा में ही डाला जाता है। गाजीपुर के 33 नालो का गन्दा पानी सीधे इसमें डाला जाता है, वही वाराणसी के 10, प्रयागराज के 32, मिर्जापुर के 16 और कानपूर के 13 नालो का गन्दा विषैला मल इसमें डाला जाता है। गंगा नदी ग्यारह राज्यों से गुजरती है और तकरीबन 40 करोड़ भारतीय अपने खेती, उद्योग और अध्यात्म को लेकर सीधे जुड़े हुए है। जानकारों ने अंदाजा लगाया की हमारे देश में गंगा जैसी नदियों के प्रदूषण से जल सम्बंधित रोगो से 10 लाख बच्चे मारे जाते है। गंगा के सफाई के लिए अभी भी इच्छा शक्ति की भारी कमी दिखती है। रोजाना 2000 मिलियन लीटर गंदा पानी साफ करने के संयंत्र पर काम किया जाना था पर सिर्फ 328 मिलियन लीटर पर ही काम हो रहा है। सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर में 68 प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किये गए पर केवल 6 ही पूरा हो पाया है। कागजो में 2061 किलोमीटर सीवर लाइन की बात है पर हकीकत में सिर्फ 66 किलोमीटर का काम ही पूरा हो पाया है। सरकार भले कुछ करे या न करे पर कुछ नागरिक इसमें भूमिका अदा कर रहे है जैसे प्रयागराज में गंगा सेना जो अपनी तरफ से गंगा की सफाई करते है। ऐसे ही कानपूर में माँ गंगा प्रदूषण मुक्ति अभियान चल रहा है। और आखिर में बिहार और उत्तर प्रदेश में अभी भी ऐसे 1400 गांव या छोटे शहर है जो गंगा के किनारे बसें है और खुले में शौच आम है। इस गन्दगी के लिए हम और आप प्रशासन को नहीं स्वयं को दोषी ठहराए ।

भूख, गरीबी और लापता होते बच्चे, भाजपा शासित प्रदेशो की जमीनी हकीकत।

उत्तर प्रदेश में हर रोज 5 कन्या लापता हो जाती है और हर हफ्ते 35 बालिकाएं। वर्ष 2018 में 3306 बच्चे लापता हो गए जिनमे से 1965 लड़किया थी।

बूट पोलिश फिल्म का एक गीत है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, आज उत्तर प्रदेश जाइये और यह गीत गाइये, बच्चा कहेगा की मेरे मुट्ठी में गरीबी, भूख और बीमारी के अलावा कुछ नहीं है। हम कहने को बहुत एडवांस हो गए है पर सच्चाई में कही नहीं है। चुनाव में बस बोल दिया जाता है, यह देंगे, वह देंगे, फिर कुछ मिलता नहीं है। सब अपने जेब भरने में लगे रहते है। चलिए थोड़ा बचपन की बात कर लेते है। कैसा बीत रहा है उत्तर प्रदेश के बच्चो का बचपन, पता करते है। उत्तर प्रदेश में हर रोज 5 कन्या लापता हो जाती है और हर हफ्ते 35 बालिकाएं। वर्ष 2018 में 3306 बच्चे लापता हो गए जिनमे से 1965 लड़किया थी। वर्ष 2020 में 1763 बच्चो के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गयी। इसमें से 92 प्रतिशत लड़कियों की उम्र 12 से 18 साल के बिच है। सुचना के अधिकार के तहत नरेश पहर ने जानकारी मांगी तो 25 जिलों ने कोई जानकारी दी नहीं। अगर पांच और राज्य जिसमे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ दे, जिसमे जयादातर भाजपा शासित प्रदेश है, कुल लापता बच्चो की संख्या वर्ष 2020 में होती है 9453. इसमें से 75 प्रतिशत यानि 7065 लड़किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के राज्य से कन्या लापता हो रही है और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। देश की राजधानी जिसमे केजरीवाल भी है और मोदी है, वहा के लापता बच्चो की संख्या 1828 है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी बुरी स्थिति में दिखाया गया है। इस रिपोर्ट में 15 प्रतिशत भारत की जनसख्या कुपोषित है। उत्तर प्रदेश की 9०1 प्रतिशत लड़किया स्कूल नहीं जाती है ।

संक्षिप्त में

उत्तर प्रदेश में निवेश की स्थिति कुछ खास नहीं है। सत्ता में आने के एक साल में निवेशक शिखर सम्मलेन किया गया। सरकार के अनुसार 1052 करार हुए जिसके जरिये 4.24 लाख करोड़ का निवेश होना था। पिछले महीने सरकार के उद्योग मंत्री ने जानकारी दी की केवल 90 करार से उद्योग शुरू हो पाया है और कुल 39 हजार करोड़ का निवेश ही हासिल हो पाया है। साफ है की प्रदेश में अब भी निवेश के लिए माहौल नहीं बन पाया है और ऊपर से भाजपा के तालाबंदी ने उद्योग जगत और बुरी मार दे दी है।

हलाकि नाम दाखिला करवाने में मौजूदा सरकार को 99 प्रतिशत कामयाबी मिली है पर कोविद काल में स्कूल के दरवाजे पिछले दो साल से बंद है। सिर्फ बच्चे उत्तरप्रदेश से लापता हो रहे है, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। भूख और दरिद्रता की कहानी भी बेहद मार्मिक है। वर्ष 2020 की रिपोर्ट सामने आई तो पता चला की तकरीबन 4 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार है। पोषण अभियान के तहत वर्ष 2021 को केंद्र सरकार ने राज्य को 56968 लाख दिए जिसमे से 19219 लाख का बजट ही खर्च हो पाया है। दूसरे शब्दों में 66 प्रतिशत बजट खर्च ही नहीं हुआ है। निति आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसमे पाया गया की भारत में सबसे ज्यादा गरीब उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखण्ड में रहते है। दो में अभी भी और एक में कुछ वक्त पहले तक भाजपा का ही शासन था। गरीबी सूचकांक में बिहार की 51 प्रतिशत आबादी, झारखंड के 42 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश के 37 प्रतिशत लोग गरीब है। जब इतनी गरीबी होगी परिवार में तो पेट के लिए रोटी भी चाहिए होगा। मोदी सरकार को लगता है पांच किलो चावल दे दो तो बस और कुछ नहीं चाहिए। पर गरीब के पेट को इतना अनाज काफी नहीं है, सत्ता के शीर्ष पर बैठे जन प्रतिनिधि को नहीं समझ आएगी। उत्तर प्रदेश में बाल मजदूरी सबसे अधिक है। पुरे भारत के कुल बाल मजदूरों का 20 प्रतिशत इसी राज्य से आते है। हलाकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई " बाल श्रमिक विद्या योजना". इसमें श्रमिकों के बच्चो को आठवीं, नौवीं और दसवीं की पढाई के लिए परिवार को सालाना 6 हजार दिया जायेगा। अभी इस योजना का लाभ 57 जिले के 2000 बच्चो को मिला पर उत्तर प्रदेश में आज भी 21,76,706 से ज्यादा बच्चे मजदूरी करते है। इनमे से 3 प्रतिशत 14 साल से कम उम्र के है। तो सरकार को मालूम है की बच्चे मजदूरी कर रहे है, गैर कानूनी तरीके से और उन्हें रोका नहीं जा सकता है, इसलिए योजना लेकर आये है। इस योजना से प्रति दिन माँ बाप को 16 रूपये मिलेगा अगर उनके बच्चे स्कूल गए तो। सरकार खैरात बाट देती है और विज्ञापन में शाबाशी की दौड शुरू हो जाती है। बाकि जिस देश में 50 हजार बच्चे रोज पैदा हो रहे हो वह पर कभी भी आभाव मिट नहीं सकता है।

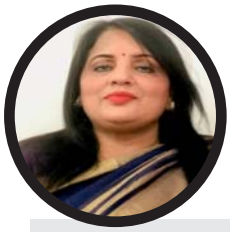

ममता शुक्ला

प्रदेश अध्यक्ष, नारी शक्ति संघटन सेल
राष्ट्रीय लोक दल

आज महिलाये अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आए दिन महिला हिंसा लगातार बढ़ रही है। जहा एक तरफ सरकार का मानना है कि महिलाएं सुरक्षित है और उनके लिए तमाम योजनाएं बनाई गई हैं मगर जब एक महिला अपनी रिपोर्ट थाने में लेकर जाती हैं तो थानेदार भी उनकी रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं होता है। सरकारी तंत्र में भी इनका कोई सुनने वाला नहीं है। यहां महिलाओं को केवल एक वस्तु समझा जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। जहां नारी शक्ति का सम्मान नहीं वह प्रदेश कभी तरक्की नहीं कर सकता है।

संक्षिप्त में

वर्ष 2018 में सरकारी बेरोजगारी विभाग में 39.93 लाख युवाओ ने स्वयं को बेरोजगार बताते हुई अपना नाम दर्ज कराया था । वर्ष 2019 में यह सांख्य 9 प्रतिशत के दर से आगे बढ़ी । सरकार ने इसी साल वादा किया की वह 2.5 लाख नौकरी देंगे । पर याद रहे की 2017 के चुनावी घोषणापत्र में 70 लाख नौकरीओ का वादा था । खैर कोविद के समय जो नौकरी पे थे वह भी बेरोजगार हो गए।

दम तोड़ती स्वास्थय व्यवस्था ।

उत्तर प्रदेश में कोरोना के समय जिस तरह से लोगो को पकड़ पकड़ के क्वारंटाइन किया जा रहा था, जिस तरह से बॉर्डर सील किये जा रहे थे, जिस तरह गरीब मजदूरों को राज्य में घुसने नहीं दिया जा रहा था, जिस तरह से शहर में सख्त तालाबंदी की गयी थी, जिस तरह से मास्क की जबरदस्ती की गयी थी, जिस तरह से एलॉपथी की चाटुकारिता की गयी थी, जिस तरह से डॉक्टर को यौद्धा बताया गया था, जिस तरह से हॉस्पिटल मानो अमृत केंद्र बन गया हो, जिस तरह से टिका को लेकर युद्ध स्तर पर तेजी दिखाई गयी, जिस तरह से महामारी के नाम पर मौलिक अधिकार छीने गए, जिस तरह से कोरोना के नाम पर जैसे मूल्य वादी सिद्धांतो की बलि चढ़ा दी गयी, उस से ऐसा लगा मानो उत्तर प्रदेश की सरकार को आम जन मानस के स्वास्थय की बेहद गंभीर चिंता हो। पर पहले समझिये की कोरोना के नाम पर जीना हराम करने वाले इन हुकमरानो के राज्य का हेल्थ सिस्टम है कैसा। इस वक्त राज्य में तकरीबन 3621 सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहे है। इसमें से 213 में बिजली की सुविधा नहीं है, 270 में नियमित पानी की सुविधा नहीं है, 459 केंद्र तक जाने के सड़के खराब स्तर पर है और 2277 डॉक्टरों की भरी कमी है। मातृत्व मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश की हालत चिंता जनक है। इस वक्त हर एक लाख शिशु जनम में 300 माताओ की मौत हो जाती है

गाओं कनेक्शन ने उन्नाओ के सरकारी प्राथमिक केंद्र का जायजा लिया तो पाया की वहा पर 15 दिन में एक बार केंद के दरवाजे खुलते है वह भी टीकाकरणके लिए। मतलब साफ है, जिसमे सरकार को मतलब है उसके लिए ही काम हो रहा है। गाओ कनेक्शन की टीम का शुक्रिया की उन्होंने कई जिलों का दौरा किया और सच्चाई बताई की कैसे कोरोना के नाम पर खुद को योद्धा बताने वाले लोग इन इलाको से नदारत है और कैसे यह सब केंद्र अपने कमी का रोना रो रहे है। शहाजनपुर जिला के खैरपुर गॉव की आशा कार्यकर्ता को डर है की किसी दिन ईमारत ही टूट के गिर जाएगी और वह उसमे दब के मर जायेंगे। फतेहपुर के बलहेरा गांव की हालत इस से अलग नहीं है। पर आप सरकारी फाइल खोलेंगे तो मिलेगा की सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र 15 स्वास्थय कर्मी का स्टाफ होना चाहिए। पर एक भी भी मिल जाये तो गनीमत है। साल 2016 में भारत में होने वाले टाइफाइड के मौतों में 49 उत्तर प्रदेश से ही है, इसी तरह से कैंसर 17 प्रतिशत और टीबी के 18 मौते इसी राज्य में होते है। अभी इस राज्यों को 5172 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1293 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद की आवश्यकता है। दुसरे शब्दों में तकरीबन 40 प्रतिशत संसाधन बढ़ाने की जरूरत है। एक और रिपोर्ट की माने तो अभी भी इस राज्य में 85 प्रतिशत झोला छाप डॉक्टर उन जगहों पर अपनी दूकान चला रहे है जहा स्वास्थय सेवाओं की कमी है। इनमे से कुछ तो 10 साल में स्वयंभू सर्जन बन गए और कुछ ने अपने हॉस्पिटल भी खोल लिए है। वर्ष 2017 में मिंट में छपी खबर के मुताबिक 91 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला डॉक्टर नहीं है और 60 प्रतिशत जगहों पर ठीक ठाक ऑपरेशन थिएटर तक नही है। भाजपा शासित इस राज्य में एक सरकारी डॉक्टर हर 19962 नागरिको के बिच है। इस के बावजूद जिस तरह से महामारी की लड़ाई का स्वांग रचा गया उस से प्रतीति हुआ की जैसे इस राज्य के हर गांव हर जिले, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर गली, हर शहर में जैसे डॉक्टर ही डॉक्टर हो। हम पूछना चाहते है की जब आप के अपने लोग सालो से हेल्थ सेवा का रोना रहे थे तब आप क्या रहे थे। तब क्यों नहीं सुध ली। तब क्यों इलाज नहीं मुहैया करवाया। अभी कोरोना में इतनी बेताबी क्यों दिखा रहे हो। क्या कोरोना से ही बचने के लिए स्वास्थय मंत्रालय बनाया आपने। क्या कोरोना की चिंता है या कोरोना के बहाने किसी और फायदे पर निगाहे टिकी है।

जय प्रकाश पवार
वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव,सर्व समाज जनता पार्टी

उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम इस वादे के साथ उतरेंगे की अगर हमारे उम्मीदवार जीते तो हम वैक्सीन के खिलाफ, तालाबंदी के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ और न्यू वर्ल्ड आर्डर के खिलाफ विधान सभा में अपनी आवाज बुलंद करेंगे।

VISIT US!
www.yatramantran.com

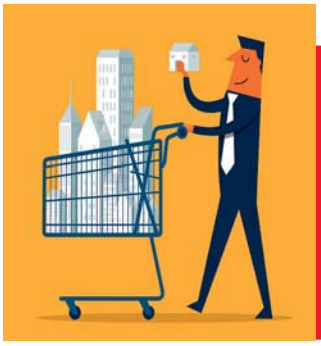

संक्षिप्त में

भाजपा को निजीकरण से बेहद प्रेम है। सब बेच दो। महज एक साल पहले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ हुए आंदोलन को कौन भूल सकता है। 21 जिले इस हड़ताल से प्रभावित हुए और बाद में सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। बता दे की पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में 35 हजार सरकारी कर्मचारी और 70 हजार लोग ठेके पर काम कर रहे है। जिस वक्त यह हड़ताल चल रही थी उस वक्त उत्तर प्रदेश का बिजली घाटा अस्सी हजार करोड़ के आस पास था।

आपराधिक मामलो के शीर्ष पर उत्तर प्रदेश

जिस राज्य की सरकार माफिया राज के सम्पूर्ण संहार की बात कह रही हो, जहा कहते है की अपराधी खुद थाने में आत्म समर्पण करता हो, जहा अवैध निर्माण चाहे किसी का भी हो, उसे जमी दोस कर दीया जाता है, जहा एनकाउंटर का नाम ही अपराधी के शरीर में सिहरन भर देता है, वहा की एक और तस्वीर भी देखना जरूरी है। यह तस्वीर भाजपा के इश्तहारों में नहीं देखने को मिलेगा। क्युकी इस बात को बताया नहीं दबाया जाता है ताकि वोट के खेल में जीत की गरंटी मिल सके। पर हम तस्वीर चाहे जैसी हो उसे बेनकाब जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश में 21 प्रतिशत आबादी दलितों की है। शायद इसीलिए इस आबादी को साधने में कोई भी राजनैतिक पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती है। मायावती से लेकर अखिलेश, हर कोई अपने दरख्त में इस दलित विकास का हिसाब लेकर बैठा है। पर दलित का हाल क्या है ? पिछले तीन साल में देश में जहा दलितों के खिलाफ आपराधिक मामले पुरे देश में 1 लाख 40 हजार केसेस थे तो इसमें अकेले उत्तरप्रदेश में 36,467 केसेस थे। इस लिहाज से दलित पर हो रहे अत्याचारो में उत्तर प्रदेश पहली पायदान में है। अब आप कहेंगे की हमारे चुने हुए लोकप्रिय और कार्य सम्राट नेता और उसमे भी खास कर के योगी जी के माननिये कुछ क्यों नहीं करते है। हां यह सवाल जब पूछ रहे है तो बता दे की हमारे माननिये भी आपराधिक रिकॉर्ड के गंगा में बेधड़क डुबकी लगाते मिल जायेंगे। इस वक्त करीब करीब ३०४ विधायक भाजपा के है। इनमे से 106 पर आपराधिक मामले चल रहे है जिसमे से 77 पर गंभीर धाराएं लगी है। जबकि समाजवादी पार्टी के 18 और बहुजन पार्टी के 15 विधायक पर आपराधिक मामले चल रहे है। भाजपा के 7 माननिये ऐसे है जिनके खिलाफ हत्या के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। जो मुख्यमंत्री कहता है की अपराधी सुधर जाओ नहीं तो ठोक दिए जाओगे, उसी के नाक के निचे उसी के माननिये अपराध का मुकदमा झेल रहे है। अब पता नहीं कौन कितनी गहरी नींद में है और कौन कितना नजर अंदाज करने की स्थिति में है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की मौत को लेकर भी उत्तर प्रदेश नंबर एक की पायदान पर है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर भी एक नजर देख लीजिये।

अखिलेन्द्र प्रताप सिंह
एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद
राष्ट्रीय महिला सुरक्षा संघ ,
राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

इस सरकार में शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। शिक्षा निति किसके लिए लाये पता नहीं विकास दुबे की हत्या हुई है उसका एनकाउंटर नहीं हुआ है। आज तक उन पुलिस वालो पर कोई करवाई नहीं हुई। एक महिला पशु चिकत्सक थी। उसका चार लोगो ने बलात्कार किया। आनन् फानन में चार लोगो का एनकाउंटर कर दिया। महिला की पहले से ही मौत हो चुकी थी। किसने इन चारो की तस्दीक की, मालूम नहीं। इनके स्मार्ट सिटी सिर्फ विज्ञापन में है, जमीन पर कही नहीं। प्रयागराज जैसे पहले था आज भी वैसा ही है।

पवन राव अम्बेडकर
राज्य महासचिव एवं प्रवक्ता
उत्तर प्रदेश,
एआईएमआईएम

वह कौन है जिन्हे गैरबराबरी के आधार पर वंचित रखा गया है। इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजति और अन्य पिछड़ा वर्ग आते है। संविधान के लागु होने के बाद भी इन्हे अपने अधिकार नहीं मिले है। १९४७ के बाद मुस्लिम को राजनीतिक अछूत बनाया गया है और उनके वोट को हासिल करके उनके हक की बात नहीं कही गयी है। हमारी पार्टी मुस्लिमों के साथ अनुसूचित जाति-जनजाति एवं पिछड़े वर्गो को साथ लेकर चल रही है। इस बार बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम प्रत्याशी भी मैदान में उतर रहे है। ब्राह्मण और ठाकुर समाज के लोगो ने भी आवेदन किया है।

वर्ष 2018 -19 में जहा 12 पुलिस हिरासत में मौते हुई वही 452 मृत्यु न्यायिक हिरासत में हुई। वर्ष 2019 -2020 में ३ मौते पुलिस हिरासत में हुआ और 400 मौते न्यायिक हिरासत में। कोविद के साल में यानि वर्ष 2020 -21 में 8 मौते पुलिस हिरासत में हुई तो 443 मौते न्यायिक हिरासत में हुई। यह वह लोग थे जो कानून और हमारी न्याय व्यवस्था से इंसाफ की गुहार लगा रहे थे और यह खुद ही दुनिया से अलविदा हो गए। अब जो जा चूका है वह तो लौटेगा नहीं फिर आप कितने ही जांच समिति बिठा दीजिये। कासगंज में अल्ताफ की मौत ने कई सवाल खड़े किये और पुलिस पर गंभीर शक पैदा किया। उत्तर प्रदेश में परचा लीक गैंग भी बेहद सक्रिय है। अगर पिछले साल का हिसाब देखे तो मामले चौकाने वाले है। पर जो बात हमारे संज्ञान में आया है, वह है पुलिस की नौकरी वाले परीक्षाओ का है। वर्ष 18 जून 2018 में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 19 लोग गिरफ्तार हुए और इनके पास अत्याधुनिक उपकरण मिले। इसी साल 29 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 51 लोगो को पकड़ा जो नकल माफिया की तरह काम कर रहे थे और सह अध्यापक परीक्षा में गलत तरह से चीटिंग मुहैया करा रहे थे। वर्ष 2017 में सह इंस्पेक्टर के परचा लीक का मामला सामने आया और SPF ने गिरफ्तारी की। वर्ष 2018 में ट्यूबवेल संचालक भर्ती परीक्षा में 11 लोगो को गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2021 दिन 29 नवंबर को शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक हुआ और 29 लोग गिरफ्तार हुए। इस परीक्षा में 20 लाख विद्यार्थी शामिल होने वाले थे।

Crime	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rape	3,467	3,025	4,816	4,246	3,964	3,065	2,769
Murder	5,150	4,732	4,889	4,324	4,018	3,806	3,779
Theft	48,380	49,491	56,550	60,434	55,614	50,197	33,250

उत्तर प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट में सबसे जयादा गिरफतारी भी देखी गई है। ड्रग के मामले में हुई इन गिरफतारी भारत में जबसे ज्यादा माना जाता है। अब तक दस हजार से ज्यादा एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे चल रहे है। जो बात हैरान करती है वह है की वर्ष 2017 से 2019 के बीच नारकोटिक कण्ट्रोल ब्यूरो के अनुसार सबसे जयादा ड्रग तस्करी के मामले महाराष्ट्र से थे जो तकरीबन 40 हजार के आस पास है। मानवाधिकारों का उल्लंघन मामले में यह राज्य सबसे आगे दीखता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट पेश की जिस मे वर्ष 2018-19 मे 40947 केसेस, 2019-20 मे ७६६२८ केसेस और २०२१ -२२ मे २४२४२ केसेस दर्ज हुए है। जब प्रधान मंत्री चुनावी रैली में गला फाड़ के कहते है की उत्तर प्रदेश में उन्होंने माफिया राज खतम किया और अब सड़क पर बहन बेटी आजाद घूम सकती है, तब उन्हें इन आकड़ो पर भी गौर कर लेना चाहिए। क्या है की चुनावी भाषण के बाद हम में से शायद ही कोई यह ढूढ़ने निकलता है की जो बोलै जा रहा है वह कितना सच बोलै जा रहा है। वर्ष 2018 के रिपोर्ट में कहा गया है की 59445 केसेस महिला अत्याचार के दर्ज हुए है जो भारत में सबसे अधिक मानी गई है। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी भी एक बड़ी समस्या है। वर्ष 2017 में 58 हजार केसेस दर्ज हुए जबकि वर्ष 2020 में यह संख्या बढ़ के हो गयी 1 लाख ७६ हजार। प्रदेश में इस समय बिजली चोरी के वारदात से निपटने के लिए 75 पुलिस स्टेशन बनाये गए है।

संक्षिप्त में

उत्तर प्रदेश में शिक्षा का सालाना बजट 66,599 करोड़ के आस पास है। कोविद महामारी के दौर में बच्चे दो साल से स्कूल नहीं गए पर जब जाते थे तब भी स्कूल का हाल कुछ खास नहीं था। 26000 हजार स्कूल ने निर्माण सम्बंधित कोई काम नहीं हुआ जबकि बजट आवंटित हो चूका था । यह बात 2020-21 की है। इटावा: जिले के 209 प्राथमिक विद्यालय मजबूरी में खुले में चल रहे थे क्युकी ईमारत जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी थी। यूपी में टोटल 1,58,839 प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, जो शहरी क्षेत्र से लेकर गांव के दूर अंचल तक स्थित है। 54,121 प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूलो में बाउंड्रीवाल नहीं हैं। 2,921 स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। आज भी प्रदेश के तकरीबन 68,630 ऐसे प्राथमिक और उच्चयतम विद्धयालय हैं, जहां बच्चों को जमीन पर बिठाकर पढ़ाया जाता है।

मुख्यमंत्री की दरियादिली के झांसे में मत आइये

माननिये प्रधान मंत्री और माननिये मुख्या मंत्री को चुनाव आते ही महिलाओ की सुख दु:ख की चिंता सताने लगी। चिंता खुद के वोट बैंक को बचाने की है बाकि अपने जेब से थोड़े ने कुछ जा रहा है। हाल ही में मोदी और योगी ने बचत गड के 16 लाख महिलाओ को 1000 करोड़ की सहायता राशि आवंटित की। इसके आलावा कन्या सुमंगला योजना के तहत अतिरिक्त 20 करोड़ की राशि घोषित की गयी है। आप मोदी के इस दरियादिली के चक्कर में न आ जाइएगा क्युकी यह पैसो की गंगा तो इसलिए बहाई जा रही है ताकि वोट की फसल काटी जा सके। मैं पूछना चाहता हु जब वर्ष 2020 में लाखो महिला श्रमिक सड़क पर पुलिस के डंडे खा रही थी, जब नवजात शिशु सड़क पर भूख से बिलख रहे थे, जब माँ सड़क पर बच्चे जन रही थी तब आपके स्मृति ईरानी कौन से कोप वास में विराजमान थी। कुछ तस्वीरें यहाँ छाप रहा हु ताकि कुछ भूले हो तो याद कर ले। बाकि जनता के टैक्स के पैसो को उड़ाना कौन सी बड़ी बात है।

देश न भूले इस तस्वीर को जब सूटकेस ही बालक के लिए बिस्तर बन गया था।

दैनिक भास्कर | 23-Apr-2020 नई दिल्ली Page10

एक महीने का मासूम गोद में, पैदल ही 850 किमी का सफर तय कर रही मां

बोली- लॉकडाउन के बाद जैसलमेर में मजदूरी बंद हुई, घर पहुंच जैसे-तैसे जी लेंगे

जैसलमेर | लॉकडाउन से देश भर के मजदूर अपने घरों के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। ऐसा ही राजस्थान में भी है। इन्हीं में शामिल हैं मध्यप्रदेश के शिवपुरी की ममता आदिवासी। ये अपने 1 माह के बच्चे को गोद में लिए 850 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने निकल पड़ी है। ममता बताती है- 'लॉकडाउन होने से काम मिलना बंद हो गया तो खाने के लाले पड़ गए। मजबूर होकर जैसलमेर से पैदल ही एमपी जाने के लिए निकल पड़े, ताकि कम से कम घर में तो रहेंगे।' ममता जैसलमेर से मंगलवार तक 150 किमी का सफर तय कर चुकी है। उसका कहना है कि घर पहुंच जाएंगे तो जैसे-तैसे जी लेंगे। यहां तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी।

मजबूरी का पैदल मार्च

जैसलमेर से बेटे को गोद में लेकर एमपी जा रही है ममता। उसके अलावा जैसलमेर से कई आदिवासी परिवार भी घरों को लौटने लगे हैं।

पुणे से बीमार मां को गोद में लिये बनारस होते हुए बिहार जा रहा एक प्रवासी।

ओ मां! अब चल नहीं पाऊंगा...

GORAKHPUR (27 March): लॉकडाउन से एक तरफ जहां पूरा शहर घरो मे कैद है वही, बेघर लोग पैदल ही अपने घर जाने को बेबस है. यह तस्वीर न सिर्फ उनकी बेबसी को दर्शाती है, बल्कि लोगों को झकझोर भी रही है. शुक्रवार को एमएमएमयूटी के पास ऐसी ही एक मां अपने बच्चे को लेकर बस्ती से देवरिया के लिए पैदल जाती मिली. 80 किमी का सफर तय कर गोरखपुर पहुंचा तो बच्चा थककर बीच सड़क पर मां का पांव पकड़कर बैठ गया. यह दृश्य ऐसा ही था, जैसे वह कह रहा हो मां अब मै थक गया हूं, नहीं चल पाऊंगा.

क्या कोरोना के नाम पर किसी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है ?

आदर्श धवन – शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता

उत्तर प्रदेश में चुनाव, और देश में ओमीक्रोन का प्रवेश। जब भी कभी आप इन समाचारों को देखें, इन पर उठाए गए कदमों को देखें तो यह सब परस्पर विरोधाभास में प्रतीत होता है। पहले ओमीकरोन और उनके प्रतिबंधों की बात करें या इसे आप कोरोना के प्रोटोकॉल (नवाचार) भी कह सकती है। सरकार का कहना है रात को 11:00 से 5:00 तक लोगों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है, और इसका कारण बताया जा रहा है ओमीक्रोन अपने पैर फैला रहा है। पहला प्रश्न यह उठता है कि ओमीकरोन अथवा कोरोना की गति रात को और दिन में क्या अलग अलग होती है, यदि होती है तो कोई इस पर शोध उपलब्ध है। और यदि ऐसा नहीं है, और यह भीड़में फैलने की संभावना ज्यादा है, जो कि सरकार का एक तर्क है। तो दिन की तुलना में रात में भीड़कहां अधिक होती है? इन दोनों का जवाब देखते हैं तो आप को संपूर्ण विरोधाभास नजर आता है। वहीं पर एक व्यक्ति ने, न्यायालय में अनुरोध किया है कि कुछ समय के लिए, जब तक कोरोना का प्रभाव है, चुनाव को टाल दिया जाए। यदि न्यायालय की अपील को मान भी लिया जाए, तो प्रश्न यह है, अब तो सब मान चुके हैं कि कोरोना हमारे जीवन का एक हिस्सा बनने जा रहा है। तो इसका क्या अर्थ यह है के चुनाव को बंद ही कर दिया जाए और भविष्य में किसी भी सांसद या विधायक का चुनाव नहीं हो। इससे यह स्पष्ट होता है की इस अपील का क्या अर्थ हो सकता है? निर्णय आपके ऊपर छोडा जाता है। न्यायालय ने चुनाव आयोग से शायद बात की है, और चुनाव आयोग अपने पर्यवेक्षक दल को विभिन्न स्थानों पर भेज रहा है।शायद वह दल वहां जाकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ ओमीक्रोन के प्रतिनिधियों से भी बात करेगा कि चुनाव तक प्रत्याशियों और मतदाताओं को तंग ना करें।आपको यह बात हास्यास्पद लग सकती है, परन्तु इन क्रियाओं का अर्थ तो यही लगता है। कुल मिलाकर आप यह समझ सकते हैं, कि यह जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं वह किसी भी विज्ञान के अनुसार, अथवा किसी भी तर्क की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। पिछले वर्ष किए गए कोरोना प्रोटोकॉल से यह स्पष्ट हो चुका है, विभिन्न प्रतिबंधों से देश के आम नागरिक को जितने दुष्प्रभाव सहने पड उतना नुक्सान करोना से नहीं हुआ। अब इसके साथ ही सरकार ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए नई वैक्सीन की अनुमति दे दी है। परंतु इन सभी टीके की अनुमति के साथ-साथ सरकारी कर्मचारी, मीडिया, चिकित्सक यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि इनमें से एक भी टीके को किसी भी संस्था ने पूर्णतया सुरक्षित नहीं माना है और यह सभी टीके अभी परीक्षण के दौर से गुजर रहे हैं। परंतु कहीं पर भी यह नहीं बताया जाता, किस वैज्ञानिक, किस चिकित्सक के कहने पर सरकार अपनी चिकित्सकीय नीतियों को निर्धारित कर रही है। जो लोग इन नीतियों का विरोध कर रहे हैं, उनकी बातों को भी तो सुनना लोकतंत्र में जननायक का कर्तव्य है। आज इस पर सब शांत बैठे ऐसा क्यों? निर्णय आपके सामने हैं, आगे आपको क्या कदम उठाने हैं यह आपको स्वयं सोचना है।

किसान आंदोलन की जीत ने देश के हुक्मशाही को साफ सन्देश दिया है की देश में अब भी कही न कही सच की लडाई लड़ ने और जीतने की हिम्मत बाकि है। पर लगातार चले इस आंदोलन में स्त्री शक्ति की मिसाल भी कायम की गयी है। यह तस्वीर उन्ही दिनों को पुनजीवित करती है जब महिलाये लंगर सेवा में सबके लिए भोजन की वयवस्था कर रही थी।

बैंक का निजीकरण

बैंक के निजीकरण के फैसले के खिलाफ सरकारी बैंक के संघटन ने मोर्चा खोल दिया है। यात्रा आमंत्रण के संग बातचीत में इस विरोध के पीछे की वजह को लेकर आल इंडिया बैंक अफसर कॉन्फिडेरशन के महासचिव सौम्य दत्ता ने अपने विचार साझा किया जो इस प्रकार से है।

₹ *भूतपूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गाँधी ने पाया की निजी बैंक लगातार विफल हो रहे है। इनके मालिक बड़े उद्योगपति है जो धन का दुरूपयोग अपने निजी फायदे के लिए कर रहे थे। वर्ष 1969 में बैंको के राष्ट्रीकरण के समय शाखाओ की सख्या 8269 थी जिसमे 1400 शाखाएं ग्रामीण भारत में थे। वर्ष 1991 में यह संख्या बढ़ के 60 हजार से जयादा हो गयी। जितने तरह के भी श्वेत क्रांति हुए वह ग्रामीण भारत में बैंको के पहुंचने से हुआ। ग्रामीणों को सस्ती बैंकिंग सुविधा मिली और वह आत्मनिर्भर हो पाए।*

Soumya Dutta
General Secretary
All India Banking Officer Federation

₹ *बैंको का निजीकरण का फैसला पुरे तरह से राजनितिक है। 1969 में भारतीय जन संघ ने बैंक के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया था। बैंको को वर्तमान सरकार बड़े उद्योगपतिओ के हवाले करना चाह रही है। इस से बैंक के डूब जाने से कोई भी आपके जमा पूंजी की जिम्मेदारी नहीं लेगा। Indusland बैंक का बैलेंस शीट ठीक नहीं है और उन्होंने मान लिया है। RBL बैंक को असमंजस की स्थिति बनी हुई है।*

₹ *अभी भारत में एक करोड़ महिलाओ द्वारा चलाये जा रहे स्वयं सहायता समूह जिसमे से 80 प्रतिशत सरकारी बैंक से जुड़े है और बहुत सस्ते दर के ब्याज पर अपने लिए सुविधा ले रहे है।*

₹ *इस समय नॉन परफार्मिंग अस्सेट्स 6.7 लाख करोड़ है, इनमे से 75 प्रतिशत कॉर्पोरेट उधारकर्ता है जिनकी देनदारी 5 लाख करोड़ से ज्यादा की है। इनके 20 प्रतिशत भी वापस आ जाये तो सरकारी बैंक को किसी तरह के अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर हो क्या रहा है हम पैसे की वसूली की जगह इन्ही को देश की संपत्ति बेच रहे है।*

संक्षिप्त में

वर्ष 2019 को इंडिया टीवी में एक खबर दिखाई गई। इस रिपोर्ट में 4000 फर्जी अध्यापक का मामला सामने आया। यह लोग एक नाम से तीन जगह पर काम कर रहे थे। एक जगह पर खुद और दो जगह पर किसी और को भेजते थे। यह एक तरह का सरकारी नौकरी में घोटाला था। प्रदेश में तकरीबन 4 लाख अध्यापक है जिसमे माना जाता है 80 हजार नकली अध्यापक है।

मोदी जी , आप जीते हो अम्बानी अडानी के लिए , देश के लिए नहीं

धनेश्वर महतो अध्यक्ष भारतीय मित्र पार्टी

ऐसा क्यों कह रहे है, क्युकी देश में भाजपा के आने के बाद से असमानता सूचकांक में भारत में तेजी से उछाल आया है। तालाबंदी के बाद से गरीब और गरीब और आमिर और आमिर हुआ है। महामारी के दौर में जहा 24 प्रतिशत आबादी की कमाई महज ३ हजार प्रति माह थी वही रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अम्बानी प्रति घंटा 90 करोड़ प्रति घंटा कमा रहे थे। इसी तरह से अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी 13 बिलियन से बढ़ के 55 बिलियन डॉलर हो गई। जहा यह एक तरफ अरबो रुपये के मालिक बन रहे थे वही अप्रैल 2020 में प्रति दिन एक लाख सत्तर हजार लोग बेरोजगार हो रहे थे। सोचिये तालाबंदी से सबके रोजगार पर ताला लगा हुआ था तब इन उद्योगपति के लिए सारे मौके क्यों उपलब्ध कराए जा रहे थे। जब मैं इस लेख पर काम कर रहा था तब खबर आई की उत्तर प्रदेश में बन रही भारत की सबसे बड़ी एक्सप्रेस वे का ठेका अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। 594 किलो मीटर मेरठ प्रयागराज का ठेका 17 हजार करोड़ में दिया गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से यह करार हुआ है। अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को 1169 करोड़ का ठेका ओडिशा राज्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 3 अप्रैल 2021 को दिया।

जबकि यह कंपनी एक महीने पहले ही स्थापित की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण केंद्र सरकार की इकाई है और इसका राज्य सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। आप एक किलो मीटर सड़क का ठेका लेने जाइये, जूते चप्पल घिस जायेंगे पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। पुराने जमाने में बादशाह जिस पर मेहरबान हो जाये उसकी निकल पड़ती थी। आज के जमाने में यह मेहरबानी कुछ चुने हुए उद्योगपतिओं में जम के बरस रहा है। अब मत पूछियेगा यहाँ बादशाह कौन है क्युकी उसे आप ही ने चुना है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की मेहरबानी ऐसी की 6 एयरपोर्ट अडानी के हवाले कर दिया गया। लखनऊ हवाई अड्डा 50 साल के लिए दे दिया गया अडानी ग्रुप को। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी की सारे ठेके इन्ही को देना पड़ रहा है। कोई सरकार से पूछे की सब कुछ इन्हे क्यों दिया जा रहा है। देश में वर्ष 2021में 1 फीसदी आबादी के पास राष्ट्रीय आय का 22 फीसदी हिस्सा है , जबकि निचले तबके के पास 13 फीसदी है।

जितने पन्नो की यह मैगजीन नहीं उस से ज्यादा तो भारत के दस उद्योगपत्तिओ पर की जा रही मेहरबानी पर लिखा जा सकता है। पर सवाल जो हम पूछ रहे है की किसी एक ही व्यक्ति को इतना ताकतवर बना देना क्या सही है, इतना विशाल आप उसे बना दो की वह सिस्टम के ऊपर काबिज हो जाये, वही हर सरकारी संपत्ति पर काबिज हो जाये। क्या देश में ऐसे कुछ गिने चुने लोगो को चुन चुन के ताकतवर बनाया जा रहा है। कुछ के हाथो में ही सारी ताकते दी जा रही है। विचार करे।

मंदिरो का भव्य इतिहास

चेतन वाढेर

अभी आप अखबार या टीवी चौनल खोले तो लगेगा, देश में दो ही जगह मंदिर है, एक अयोध्या और दूसरा वाराणसी। पर हमारा देश धार्मिक पर्यटन के एक भव्य और विशाल इतिहास समेटे हुए है। यहाँ के हर कोने में मंदिर के वास्तुशिल्प और उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। अगली बार जब आप यात्रा की योजना बनाये तो सूचि में इन मंदिरो के सैर को अवश्य शामिल करे। इंग्लैंड में रहते हुए बस यही खवाइश है की हमारे इन बेशकीमती धरोहर की सुरक्षा हो और विश्व पटल पर यह सबके संज्ञान में आये। ज्यादा से ज्यादा जन मानस तक इन मंदिरो की जानकारी पहुंचे।

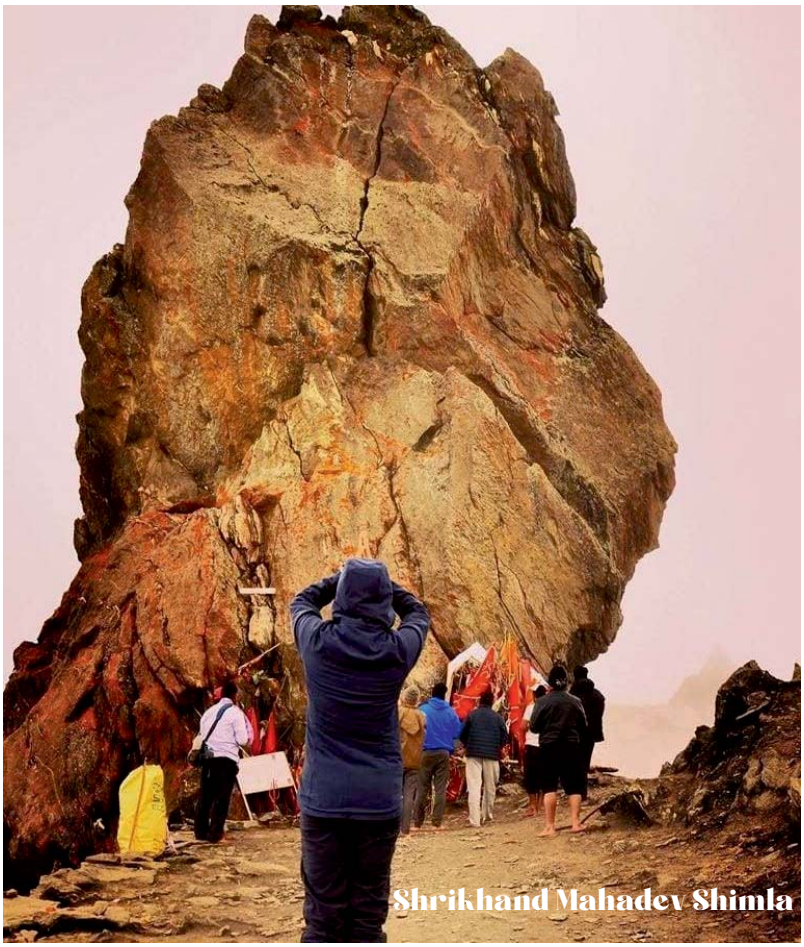

श्रीखंड महादेव भगवान शिव का निवास स्थली है और हिन्दुओ का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। कैलाश पर्वत में जिन पांच जगहों को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, उनमे से एक यह है। 72 फीट का यह शिव लिंग पहाड़ो से ढके हिम शिखर पर है। शिमला से आगे उममंडल के निरमंड भाग के तकरीबन 18 हजार फीट के उचाई पर हिमखंड के मध्य यह शिव लिंग है।

कर्णाटक के हसन शहर से ३५ किलोमीटर दूर हरनहाली में है यह खूबसूरत और भव्य लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, होयसला के राजा वीरा सोमेश्वर ने भगवन विष्णु के इस मंदिर को सन 1235 को बनाया था। मंदिर के तीन भाग है जिसमे भगवन विष्णु वेणुगोपाल, केशव और नरसिम्हा के रूप में है।

ओडिशा के जिला गंजम के कुंतेश्वरी पहाड़ में है माँ कुंतेश्वरी का यह मंदिर।

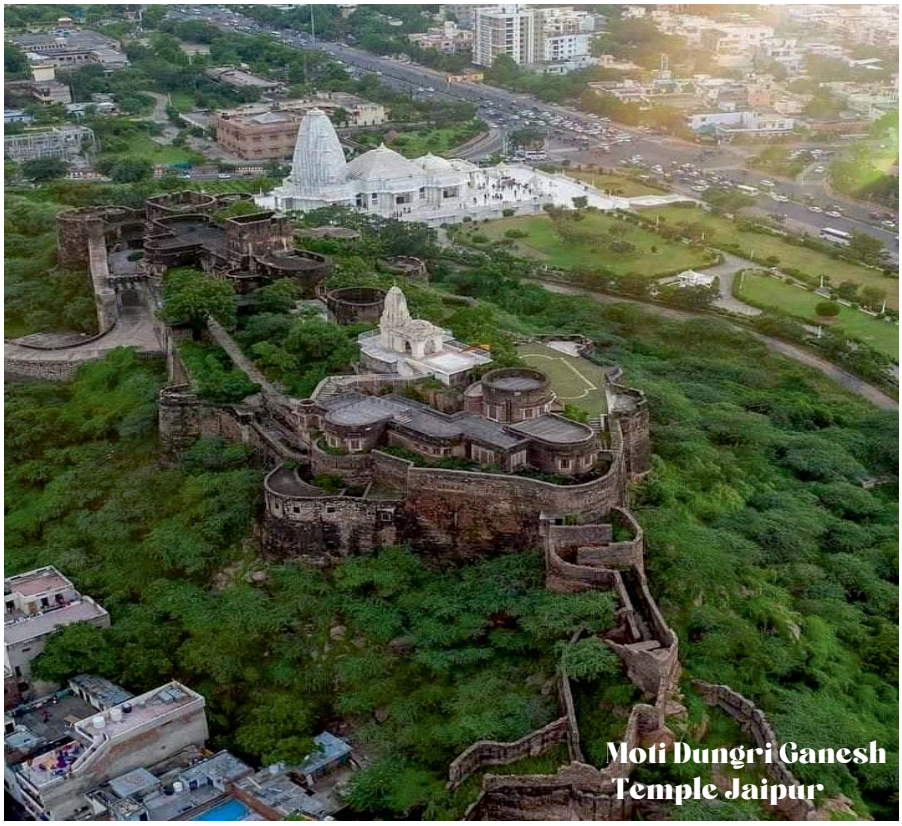

मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर राजस्थान यह मंदिर भगवन गणेश को समर्पित है। सेठ जय राम पल्लीवाल ने 1761 को इसका निर्माण करवाया था। आज यह एक प्रमुख धार्मिक स्थल है पर्यटक के नजर से।

इंद्रायणी नदी के तट में बना यह पुणे के सबसे बड़े मंदिरो में एक है। मंदिर के प्रवेश में संत तुकाराम की मूर्ति है जो देहु में जनम लिए थे। संत तुकाराम के गाथाओ को इस मंदिर के दीवारों को उकेरित किया गया है। इस मंदिर का निर्माण १९२३ को किया गया था।

थंजावुर के राजा चोला ने इस विशाल मंदिर को सन 1010 ईस्वी में बनाया था। पिछले साल सितम्बर में इस मंदिर ने एक हजार साल पुरे कर लिए है।

तमिलनाडु के थिरुवर ललितंबीगई समिधा मेगनाथा स्वामी मंदिर है।

चीन की दीवार के बाद सबसे लम्बी दीवार भारत में है। बहुत से भारतीओ को पता ही नहीं है की मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले की दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लम्बी दीवार है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसके निर्माण में 15 वर्ष लगे थे। सन 1446 से 1458 के बीच इसका निर्माण किया गया है। यह दीवार 36 किलोमीटर लम्बी है और 15 फीट चौड़ी है। इसमें एक साथ दस घोड़े दौड़ सकते है।

HRAHIN/2017/72144

Rajiv Dixit Memorial

Hospital & Institute of Integrated Medical Sciences

Dr. Amar Singh Azad
MBBS, MD

Dr. Biswaroop Roy Chowdhury
Ph.D (Diabetes)

Acharya Manish
(Ayurveda Guru)

Dr. Awadhesh Pandey
MBBS, MD

Devinagar, Delhi highway, Dera Bassi (Chandigarh)

We believe: "To Cure, remove the cause"

Contact us at:

Phone : 7827710735

www.biswaroop.com/chdhospital

Postural Medicine • Allopathy • Homeopathy • Ayurveda • Naturopathy